



## भारत में उर्वरक सब्सिडी वितरण का विश्लेषण

विजय कुमार<sup>1</sup>, महा सिंह<sup>1</sup>, किरण कुमारी<sup>1</sup>

### सारांश

**पृष्ठभूमि:** उर्वरक सब्सिडी भारत की कृषि नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो किसानों को उर्वरकों की सुलभ एवं किफायती उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ देश की खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करती है। किन्तु सब्सिडी पर बढ़ता हुआ राजकोषीय व्यय, यूरिया पर अत्यधिक निर्भरता तथा पोषक तत्वों के असंतुलित उपयोग ने वर्तमान उर्वरक सब्सिडी व्यवस्था की आर्थिक एवं पर्यावरणीय स्थिरता पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य वर्ष 2001-2002 से 2022-2023 के दौरान भारत में उर्वरक सब्सिडी वितरण की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना तथा सब्सिडी आवंटन की बदलती संरचना का अध्ययन करना है।

**विधियाँ:** यह अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है, जिन्हें विभिन्न सरकारी प्रकाशनों एवं आधिकारिक प्रतिवेदनों से संकलित किया गया। कुल उर्वरक सब्सिडी, पोषक तत्व-वार सब्सिडी वितरण तथा वर्ष 2010 में लागू की गई पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (Nutrient Based Subsidy: NBS) योजना सहित प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेपों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए वर्णनात्मक सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग किया गया।

**परिणाम:** अध्ययन से ज्ञात हुआ कि भारत में उर्वरक सब्सिडी वर्ष 2001-2002 में ₹ 12,695.02 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-2023 में ₹ 2,54,798.88 करोड़ के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुँच गई। यह वृद्धि मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय उर्वरक कीमतों में वृद्धि, घरेलू मांग में विस्तार तथा कोविड-19 महामारी के दौरान आपूर्ति श्रृंखला में उत्पन्न व्यवधानों के कारण हुई। यद्यपि वर्ष 2010 में संतुलित पोषक तत्व उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से NBS योजना लागू की गई, फिर भी कुल सब्सिडी में यूरिया का सर्वाधिक हिस्सा बना रहा, जिसके परिणामस्वरूप यूरिया का अत्यधिक उपयोग, पोषक तत्वों का असंतुलन तथा पर्यावरणीय क्षति जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुईं। अध्ययन के निष्कर्ष संकेत देते हैं कि उर्वरक सब्सिडी प्रणाली की दक्षता, राजकोषीय स्थिरता तथा पर्यावरणीय सततता को सुदृढ़ करने के लिए यूरिया को NBS व्यवस्था के अंतर्गत शामिल करना, संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देना तथा जैविक एवं वैकल्पिक पोषक स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

**मुख्य शब्द:** कृषि नीति, उर्वरक सब्सिडी, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS), संतुलित उर्वरीकरण, यूरिया।

## Analysis of Fertilizer Subsidy Disbursements in India

Vijay Kumar<sup>1</sup>, Maha Singh<sup>1</sup>, Kiran Kumari<sup>1</sup>

10.18805/BKAP804

### ABSTRACT

**Background:** Fertilizer subsidy is a key component of India's agricultural policy, ensuring the availability of fertilizers at affordable prices and supporting national food security. However, the increasing fiscal burden of subsidies, coupled with excessive dependence on urea and imbalanced nutrient application, has raised concerns regarding the long-term economic and environmental sustainability of the existing subsidy regime. The present study was undertaken to analyse the trends in fertilizer subsidy disbursements in India and to examine the changing composition of subsidy allocation during 2001-2002 to 2022-2023.

**Methods:** The study was based on secondary data collected from official publications and government reports. Fertilizer subsidy trends were analysed using descriptive statistical techniques to assess changes in total subsidy expenditure, nutrient-wise subsidy allocation, and the impact of major policy interventions, including the introduction of the Nutrient Based Subsidy (NBS) scheme in 2010.

**Result:** The analysis revealed that fertilizer subsidy increased substantially from ₹12,695.02 crore in 2001-2002 to a record ₹ 2,54,798.88 crore in 2022-2023, primarily due to rising international fertilizer prices, increased domestic demand, and supply disruptions during the COVID-19 pandemic. Although the NBS scheme was introduced to encourage balanced nutrient use, urea continued to receive the largest share of subsidies, leading to excessive consumption, nutrient imbalance, and adverse environmental consequences. The findings highlight the need for comprehensive policy reforms, including the integration of urea under the NBS framework, promotion of balanced fertilization practices and greater encouragement of organic and alternative nutrient sources to improve the efficiency, fiscal sustainability and environmental performance of India's fertilizer subsidy system.

**Key words:** Agricultural policy, Balanced fertilization, Fertilizer subsidy, Nutrient based subsidy, Urea.

### परिचय

भारत अपनी कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था के कारण विश्व में उर्वरकों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। उर्वरक फसल उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर मुख्य फसलों जैसे चावल, गेहूँ और गन्ने में। भारतीय सरकार ने किसानों को सस्ती उर्वरक उपलब्ध कराने और खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए दशकों से उर्वरक सब्सिडी लागू की है, विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद।

भारत में उर्वरक सब्सिडी प्रणाली का आकार काफी बढ़ गया है, खासकर उर्वरकों की बढ़ती वैश्विक कीमतों और घरेलू मांग में वृद्धि के कारण। हालांकि, इस सब्सिडी प्रणाली ने सरकार की

<sup>1</sup>Krishi Vigyan Kendra, Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Uchani, Karnal-132 001, Haryana, India.

**Corresponding Author:** Vijay Kumar, Krishi Vigyan Kendra, Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Uchani, Karnal-132 001, Haryana, India.  
Email: v\_jay1977@hau.ac.in

**How to cite this article:** Kumar, V., Singh, M. and Kumari, K. (2026). Analysis of Fertilizer Subsidy Disbursements in India. *Bhartiya Krishi Anusandhan Patrika*. 41(2): 123-129. doi: 10.18805/BKAP804.

**Submitted:** 08-10-2024 **Accepted:** 05-05-2026 **Online:** 29-06-2026

वित्तीय स्थिति पर बोझ, पोषक तत्वों के असंतुलन और पर्यावरणीय क्षरण जैसी चुनौतियां भी पैदा की हैं। उर्वरक सब्सिडी, जो मूल्य निर्धारण में हस्तक्षेप का एक हिस्सा है, 1976-77 में केवल ₹ 60 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 1,40,122.32 करोड़ हो गई है, जो अब तक की सबसे अधिक है (Mankunnummal Ajil, 2022)। यह शोध पत्र 2001 से 2023 तक उर्वरक सब्सिडी वितरण के रुझानों की जांच करता है, जिसमें यूरिया और अनियंत्रित उर्वरकों [फॉस्फोरस (P) और पोटैश (K)] के बीच बदलते समीकरणों का विश्लेषण किया गया है।

### उद्देश्य

इस शोध पत्र के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. 2001 से 2023 तक उर्वरक सब्सिडी वितरण के रुझानों का विश्लेषण करना।
2. यूरिया और अनियंत्रित उर्वरकों (P & K) के बीच सब्सिडी के वितरण का मूल्यांकन करना।
3. बढ़ती उर्वरक सब्सिडी का सरकार की वित्तीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका आकलन करना।
4. सब्सिडी तंत्र में पोषक तत्वों के असंतुलन और स्थिरता संबंधी चुनौतियों का मूल्यांकन करना।

### सामग्री एवं परीक्षण विधि

इस शोध में उपयोग किए गए डेटा को भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा प्रकाशित विभिन्न आधिकारिक सरकारी स्रोतों, रिपोर्टों और उर्वरक सब्सिडी पर बजट दस्तावेजों से एकत्र किया गया है। विश्लेषण किए गए प्रमुख पैरामीटर निम्नलिखित हैं:

1. **अनियंत्रित उर्वरकों (P & K) पर सब्सिडी वितरण:** प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए स्वदेशी और आयातित P & K उर्वरकों पर सब्सिडी का डेटा 2001-2023 के बीच एकत्र किया गया।
2. **यूरिया पर सब्सिडी वितरण:** अध्ययन अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए स्वदेशी और आयातित यूरिया के बीच अंतर को ध्यान में रखते हुए डेटा एकत्र किया गया।
3. **कुल सब्सिडी वितरण:** यूरिया और गैर-यूरिया (P & K) उर्वरकों दोनों को शामिल करते हुए कुल उर्वरक सब्सिडी की गणना की गई ताकि 22 साल की अवधि में रुझानों की पहचान की जा सके।

अध्ययन में डेटा की वर्णनात्मक विश्लेषण पद्धति का उपयोग किया गया, जिससे सब्सिडी वितरण में वर्षों के दौरान प्रमुख रुझानों और परिवर्तनों को उजागर किया गया। इसके अलावा, वैश्विक कारकों जैसे मूल्य अस्थिरता और पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना जैसी घरेलू नीति सुधारों को सब्सिडी वितरण पर उनके प्रभाव को समझने के लिए विचार किया गया (Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India, 2023)।

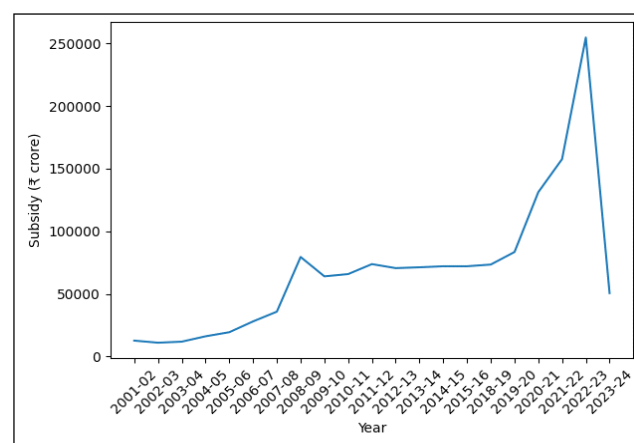
केंद्रीय सब्सिडी के लिए सभी वर्णनात्मक सांख्यिकी तथा वृद्धि गणनाएँ, जैसे AGR और CAGR की गणना की गई है।

### परिणाम एवं विवेचना

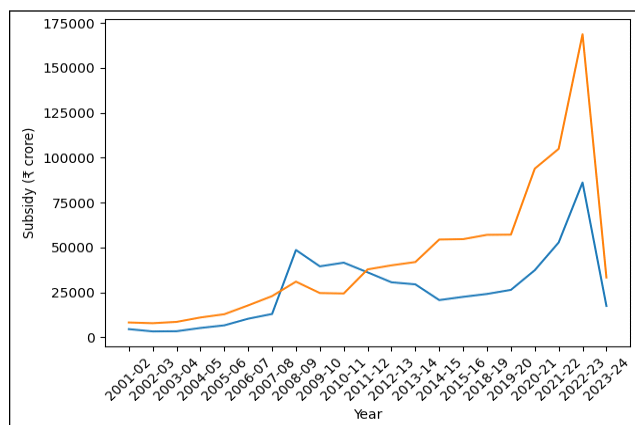
#### उर्वरक सब्सिडी वितरण के रुझान (2001-2023)

भारत में उर्वरक सब्सिडी वितरण में साल दर साल उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो बढ़ती मांग, वैश्विक उर्वरक कीमतों में वृद्धि और नीतिगत परिवर्तनों को दर्शाती है। किसानों को उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से सब्सिडी वाले 24 प्रकार के फॉस्फोरस एवं पोटैश (P&K) उर्वरक, जिसमें यूरिया शामिल हैं, उपलब्ध कराए जाते हैं (Arbiya and Sheereen 2022)।

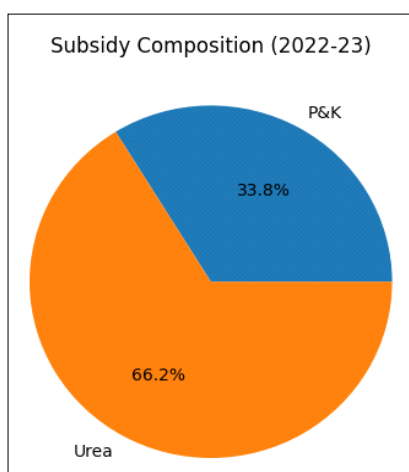
- **2001-2005:** 2000 के दशक की शुरुआत में, उर्वरक सब्सिडी वितरण में स्थिरता देखी गई। 2001-2002 में कुल सब्सिडी ₹ 12,695.02 करोड़ थी, जिसमें यूरिया का प्रमुख हिस्सा था। 2004-2005 तक, कुल सब्सिडी बढ़कर ₹ 16,127.70 करोड़ हो गई, मुख्यतः वैश्विक उर्वरक कीमतों में वृद्धि के कारण।
- **आरेख 1** से स्पष्ट होता है कि भारत में वर्ष 2001-02 से 2022-23 तक उर्वरक सब्सिडी में निरंतर वृद्धि हुई है। प्रारम्भिक वर्षों में वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी रही, जबकि 2020-21 के बाद इसमें तीव्र बढ़ोतरी दर्ज की गई। वर्ष 2022-23 में कुल उर्वरक सब्सिडी ₹ 2,54,798.88 करोड़ के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जो वैश्विक मूल्य वृद्धि एवं आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों का परिणाम था।
- **2008-2009 की वृद्धि:** 2008-2009 में सब्सिडी वितरण में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, जो ₹ 99,494.71 करोड़ तक पहुंच गई (जिसमें नकद और बॉन्ड दोनों शामिल थे)। यह वैश्विक वित्तीय संकट और अंतरराष्ट्रीय उर्वरक कीमतों में तेजी के कारण था।
- **आरेख 2** दर्शाता है कि अध्ययन अवधि के दौरान यूरिया पर दी जाने वाली सब्सिडी का हिस्सा फॉस्फोरस एवं पोटैश (P&K) उर्वरकों की तुलना में अधिक रहा है। वर्ष 2020-21 के बाद यूरिया सब्सिडी में तीव्र वृद्धि देखी गई, जिससे दोनों श्रेणियों के बीच का अंतर और अधिक बढ़ गया। यह प्रवृत्ति भारतीय कृषि में यूरिया के अधिक उपयोग को इंगित करती है।



आरेख 1: कुल उर्वरक सब्सिडी का रुझान (2001-02 to 2023-24)।



**आरेख 2:** भारत में फास्फोरस-पोटाश तथा यूरिया उर्वरकों पर सब्सिडी का तुलनात्मक रुझान (2001-02 to 2023-24)।



**आरेख 3:** वर्ष 2022-23 में उर्वरक सब्सिडी की संरचना (प्रतिशत में)।

- आरेख 3 से ज्ञात होता है कि वर्ष 2022-23 में कुल उर्वरक सब्सिडी का 66.2% हिस्सा यूरिया पर तथा 33.8% हिस्सा फास्फोरस एवं पोटाश (P&K) उर्वरकों पर व्यय किया गया। इससे स्पष्ट है कि उर्वरक सब्सिडी वितरण में यूरिया का प्रभुत्व बना हुआ है। यह स्थिति पोषक तत्वों के असंतुलित उपयोग की ओर संकेत करती है।
- **एनबीएस की शुरुआत (2010):** 2010 में शुरू की गई न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) योजना ने एक स्थिर सब्सिडी प्रणाली से उर्वरकों के पोषक तत्व सामग्री पर आधारित प्रणाली की ओर ध्यान केंद्रित किया। 2010-2011 तक, कुल उर्वरक सब्सिडी बढ़कर ₹ 65,836.68 करोड़ हो गई, जिसमें से यूरिया को ₹ 24,336.68 करोड़ की सब्सिडी मिली।
- **हालिया वर्ष (2020-2023):** COVID-19 महामारी और इसके बाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान ने उर्वरक कीमतों में तेज वृद्धि की। 2022-2023 तक, कुल सब्सिडी वितरण ₹ 2,54,798.88 करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया, जिससे भारतीय सरकार पर महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ पड़ा।

## प्रमुख निष्कर्ष और विश्लेषण

**भारत में उर्वरकों पर वितरित सब्सिडी की राशि का विवरण**

तालिका 1 से स्पष्ट होता है कि भारत में उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी में वर्ष 2001-02 से 2022-23 तक उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2001-02 में कुल उर्वरक सब्सिडी ₹ 12,695.02 करोड़ थी, जो बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 2,54,798.88 करोड़ के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई। इस अवधि में विशेष रूप से यूरिया पर दी जाने वाली सब्सिडी का हिस्सा अधिक रहा, जबकि फास्फोरस एवं पोटाश (P&K) उर्वरकों पर भी पर्याप्त रियायत प्रदान की गई। वर्ष 2020-21 के बाद वैश्विक उर्वरक कीमतों में वृद्धि, आयात लागत में बढ़ोतरी तथा किसानों को उर्वरक सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने की सरकारी नीति के कारण सब्सिडी व्यय में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय कृषि क्षेत्र की उत्पादकता एवं खाद्य सुरक्षा बनाए रखने में उर्वरक सब्सिडी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, हालांकि इसके कारण सरकार पर वित्तीय भार भी निरंतर बढ़ा है।

## प्रमुख विश्लेषण बिन्दु:

### 1. शुरुआती साल (2001-2005): स्थिर सब्सिडी

- 2001-2002 में, उर्वरकों पर कुल सब्सिडी ₹ 12,695.02 करोड़ थी, जिसमें से 60% से अधिक हिस्सा यूरिया सब्सिडी के रूप में आवंटित किया गया था (₹ 8,191.50 करोड़)। यह मुख्य फसलों जैसे गेहूँ और चावल के लिए यूरिया की उच्च मांग को दर्शाता है।
- अनियंत्रित उर्वरकों (P & K) पर दी गई सब्सिडी 2001-2002 में ₹ 4,503.52 करोड़ थी, जो 2005-2006 तक बढ़कर ₹ 6,596.19 करोड़ हो गई।

### 2. 2007-2008 (बॉन्ड जारी और बढ़ी हुई सब्सिडी)

- 2007-2008 में वैश्विक उर्वरक कीमतों में वृद्धि के कारण सब्सिडी प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव आया। नकद सब्सिडी के अलावा, सरकार ने उर्वरक आयात की बढ़ती लागत की भरपाई के लिए ₹ 7,500 करोड़ के बॉन्ड जारी किए। उस वर्ष नकद सब्सिडी वितरण कुल ₹ 35,819.16 करोड़ थी, जो सस्ती उर्वरक कीमतों को बनाए रखने के बढ़ते वित्तीय बोझ को दर्शाती है।

### 3. 2008-2009 (सब्सिडी वितरण में वृद्धि)

- 2008-2009 में कुल उर्वरक सब्सिडी वितरण में नाटकीय वृद्धि हुई, जो नकद और बॉन्ड दोनों को मिलाकर ₹ 99,494.71 करोड़ तक पहुँच गई। यह अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी और घरेलू मांग में वृद्धि के संयोजन के कारण था।
- उस वर्ष कुल नकद सब्सिडी ₹ 79,494.71 करोड़ थी, जिसमें से अनियंत्रित उर्वरकों के लिए ₹ 48,554.79 करोड़ और यूरिया (स्वदेशी और आयातित) के लिए ₹ 30,939.92 करोड़ का वितरण किया गया था। यह सरकार पर पड़े भारी वित्तीय दबाव को दर्शाता है, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतों दोनों को प्रबंधित करने के लिए संघर्ष कर रही थी।

### 4. 2010-2015 (न्यूट्रिएंट-बेस्ड सब्सिडी (NBS) का कार्यान्वयन)

- 2010 में एनबीएस योजना के कार्यान्वयन ने विशेष रूप से गैर-यूरिया उर्वरकों के लिए सब्सिडी आवंटन में बदलाव किया।

**तालिका 1:** भारत में उर्वरकों पर वितरित सब्सिडी की राशि (सकल), 2001–2002 से 2023–2024 (17.07.2023) तक। (रुपये करोड़ में)

वर्ष	विनियंत्रित उर्वरक (स्वदेशी, आयातित) पर वितरित रियायत की राशि			यूरिया पर वितरित सब्सिडी की राशि			कुल उर्वरक
	स्वदेशी	आयातित	कुल	स्वदेशी	आयातित	कुल	
	फास्फोरस (पी)	फास्फोरस (पी)		यूरिया	यूरिया		
	और पोटेशियम (K)	और पोटेशियम (K)					
2001-2002	3759.52	744.00	4503.52	8044.00	147.50	8191.50	12695.02
2002-2003	2487.94	736.58	3224.52	7790.00	1.16	7791.16	11015.68
2003-2004	2606.00	720.00	3326.00	8521.00	0.82	8521.82	11847.82
2004-2005	3977.00	1165.18	5142.18	10243.15	742.37	10985.52	16127.70
2005-2006	4499.20	2096.99	6596.19	10652.57	2140.88	12793.45	19389.64
2006-2007	6648.17	3649.95	10298.12	12650.37	3071.06	17721.43	28019.55
2007-2008 (नकद)	7833.80	5100.00	12933.80	12950.37	9934.99	22885.36	35819.16
2007-2008 (बांड)	2500.00	1500.00	4000.00	3500.00	-	3500.00	7500.00
2008-2009 (नकद)	24707.10	23847.69	48554.79	17968.74	12971.18	30939.92	79494.71
2008-2009 (बांड)	8250.00	8750.00	17000.00	3000.00	-	3000.00	20000.00
2009-2010	16000.00	23452.06	39452.06	17580.25	6999.98	24580.23	64032.29
2010-2011	20650.00	20850.00	41500.00	15081.00	6454.00	24336.68	65836.68
2011-2012	20137.49	16571.92	36107.94	20208.00	13716.00	37760.00	73790.90
2012-2013	16000.00	14576.10	30576.12	20000.00	15133.00	40016.00	70592.13
2013-2014	15500.00	13926.86	29426.86	26500.00	11538.00	41853.00	71251.22
2014-2015	12000.00	8667.30	20667.30	38200.01	16200.00	54400.00	72070.30
2015-2016	8998.73	6257.58	22468.56	34863.97	12300.00	54600.00	72070.30
2015-2016 (Revised estimates)	-	-	21937.56	-	-	-	-
2016-2017	-	-	19000.01	-	-	-	-
2017-2018	-	-	22237.00	-	-	-	-
2018-2019	-	-	24080.35	-	-	-	73435.21
2019-2020	-	-	26335.00	-	-	57099.00	83467.85
2020-2021	22288.36	15015.37	37303.73	68807.41	25049.62	93857.03	131229.50
2021-2022	31931.46	20795.74	52727.20	54619.72	50250.40	104870.12	157640.63
2022-2023	50089.67	36032.56	86122.23	127311.05	41365.60	168676.65	254798.88
2023-2024- upto 17.07.2023	9794.02	7593.72	17387.74	28656.00	4565.31	33221.31	50609.05

Source: <https://www.indiastat.com/table/economy/amount-subsidy-gross-disbursed-fertilisers-india-2/462385>

2010–2011 में कुल सब्सिडी ₹ 65,836.68 करोड़ थी, जिसमें से यूरिया को ₹ 24,336.68 करोड़ और अनियंत्रित उर्वरकों को ₹ 41,500 करोड़ की सब्सिडी दी गई।

- 2014–2015 तक, कुल सब्सिडी वितरण ₹ 72,070.30 करोड़ पर स्थिर हो गया, हालांकि अधिकांश हिस्सा अभी भी यूरिया को आवंटित किया गया, जो भारतीय कृषि में नाइट्रोजन-आधारित उर्वरकों के प्रभुत्व को दर्शाता है।

#### 5. 2015 के बाद (बढ़ती सब्सिडी और वैश्विक बाजार अस्थिरता)

- 2015 के बाद, वैश्विक बाजार की अस्थिरता और भारत में बढ़ती उर्वरक मांग ने सब्सिडी बढ़ा दी। 2019–2020 में कुल सब्सिडी वितरण ₹ 83,467.85 करोड़ था, जिसमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा (₹ 57,099 करोड़) यूरिया सब्सिडी के लिए आवंटित किया गया था।
- इस अवधि में गैर-यूरिया उर्वरकों, विशेष रूप से फॉस्फोरस और पोटैश के लिए भी सब्सिडी में धीरे-धीरे वृद्धि देखी गई, जो

संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों का हिस्सा थी।

#### 6. 2020–2023 (रिकॉर्ड उच्च सब्सिडी)

- 2020–2023 की अवधि में COVID–19 महामारी के दौरान वैश्विक उर्वरक कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण रिकॉर्ड उच्च सब्सिडी देखी गई।
- 2020–2021 में, कुल उर्वरक सब्सिडी वितरण सर्वकालिक उच्च ₹ 1,31,229.50 करोड़ तक पहुँच गया, जिसमें यूरिया सब्सिडी ₹ 93,857.03 करोड़ थी।
- अगले वर्ष (2021–2022) में और वृद्धि हुई, जिसमें कुल सब्सिडी ₹ 1,57,640.63 करोड़ तक पहुँच गई, जिसमें से ₹ 1,04,870.12 करोड़ यूरिया के लिए आवंटित की गई थी। इसने सरकार की वित्तीय स्थिति पर महत्वपूर्ण बोझ डाला।
- 2022–2023 तक, कुल सब्सिडी वितरण ₹ 2,54,798.88 करोड़ तक पहुँच गया, जो उर्वरकों, विशेष रूप से फॉस्फोरस और पोटैश

की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेज वृद्धि को दर्शाता है। यह वर्ष भारत में उर्वरक सब्सिडी वितरण में अब तक के सबसे उच्च स्तर को चिह्नित करता है।

### 7. 2023–2024 (प्रक्षेपित रुझान)

- 17 जुलाई, 2023 तक, उर्वरकों के लिए कुल सब्सिडी वितरण ₹ 50,609.05 करोड़ था। इसमें से ₹ 33,221.31 करोड़ यूरिया और ₹ 17,387.74 करोड़ गैर-यूरिया उर्वरकों के लिए आवंटित किया गया था। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वित्तीय वर्ष के लिए सब्सिडी का बोझ उंचा बना रहेगा।

### यूरिया और अनियंत्रित उर्वरकों के बीच वितरण

पिछले वर्षों में, यूरिया ने कुल सब्सिडी वितरण का प्रमुख हिस्सा बनाए रखा है। 2020–2021 में, यूरिया की सब्सिडी ₹ 93,857.03 करोड़ थी, जबकि अनियंत्रित उर्वरकों (फॉस्फोरस और पोटाश) के लिए ₹ 37,303.73 करोड़ दिए गए। यह प्रवृत्ति यूरिया पर असमान ध्यान केंद्रित करने का संकेत देती है, जिससे भारतीय कृषि में पोषक तत्वों का असंतुलन हो गया है।

### मुख्य मुद्दे:

- पोषक तत्व असंतुलन:** यूरिया पर अत्यधिक निर्भरता से नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P), और पोटैशियम (K) के अनुपात में असंतुलन पैदा हो गया है, जिससे मिट्टी की उर्वरता और फसल की उत्पादकता प्रभावित हुई है।
- राजकोषीय दबाव:** यूरिया पर बढ़ती सब्सिडी से सरकार की वित्तीय स्थिति पर भारी दबाव पड़ा है, विशेषकर घरेलू और आयातित यूरिया की कीमतों को नियंत्रित करने की आवश्यकता के कारण।

### बढ़ती उर्वरक सब्सिडियों का सरकार के वित्त पर राजकोषीय प्रभाव

2001–2023 के अध्ययन अवधि में, उर्वरक सब्सिडियों का राजकोष पर प्रभाव काफी बढ़ गया है। 2001–2002 में सब्सिडी ₹ 12,695.02 करोड़ से बढ़कर 2022–2023 में ₹ 2,54,798.88 करोड़ हो गई।

- 2008 से पहले:** सब्सिडियों का बोझ धीरे-धीरे बढ़ रहा था।
- 2010 के बाद:** न्यूट्रिएंट-बेस्ड सब्सिडी (NBS) योजना की शुरुआत से सब्सिडी में वृद्धि थोड़ी कम हुई।
- हाल के वर्ष:** कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान से वित्तीय बोझ बढ़ गया।

Economic Survey of India (2022) के अनुसार, कृषि उत्पादकता बनाए रखने में उर्वरक सब्सिडी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, हालांकि इससे राजकोषीय दबाव में भी वृद्धि हुई है।

### सब्सिडी प्रणाली की चुनौतियाँ – पोषक तत्व असंतुलन और स्थिरता चिंताएँ

वर्तमान सब्सिडी प्रणाली में यूरिया पर ध्यान केंद्रित करने से भारतीय कृषि में पोषक तत्वों का असंतुलन हो गया है, जो दीर्घकालिक कृषि उत्पादकता और मिट्टी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है।

- यूरिया का अत्यधिक उपयोग:** 2020–2021 में यूरिया की सब्सिडी कुल ₹ 1,31,229.50 करोड़ में से ₹ 93,857.03 करोड़ थी, जो कुल उर्वरक सब्सिडी का 71.5% थी।
- पर्यावरणीय गिरावट:** यूरिया के अत्यधिक उपयोग से भूजल प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ा है।

सरकार के प्रयासों के बावजूद, उर्वरक सब्सिडी प्रणाली यूरिया के पक्ष में झुकी हुई है। भविष्य में, पोषक तत्व असंतुलन को दूर करने और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नीति सुधार आवश्यक हैं।

### केंद्रीय सरकार की उर्वरक एवं खाद्य सब्सिडी प्रवृत्तियाँ (1976–2023)

तालिका 2 में वर्ष 1976–77 से 2022–23 (संशोधित अनुमान) तक केंद्र सरकार के स्तर पर उर्वरक और खाद्य सब्सिडी का समेकित विवरण प्रस्तुत किया गया है। यह आँकड़े आधिकारिक रूप से प्रकाशित सब्सिडी अभिलेखों और बजटीय डेटा पर आधारित हैं। तालिका में वर्तमान मूल्यों (₹ करोड़) में सब्सिडी की वास्तविक राशि के साथ-साथ वार्षिक वृद्धि दर (AGR), 5-वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक

तालिका 2: भारत में केंद्रीय सरकार की उर्वरक एवं खाद्य सब्सिडी प्रवृत्तियाँ।

(₹ करोड़, वर्तमान मूल्य)

वर्ष	उर्वरक सब्सिडी	AGR (%)	CAGR (%)	खाद्य सब्सिडी	AGR (%)	CAGR (%)	कुल सब्सिडी	उर्वरक हिस्सा (%)	खाद्य हिस्सा (%)
1976-77	377	-	-	811	-	-	1,188	31.7	68.3
1980-81	889	23.3	22.7	1,600	18.6	18.5	2,489	35.7	64.3
1985-86	2,222	19.6	21.9	2,679	10.8	10.5	4,901	45.3	54.7
1990-91	4,389	12.2	14.6	2,850	1.3	1.2	7,239	60.6	39.4
1995-96	7,570	12.0	11.5	7,113	19.6	20.1	14,683	51.5	48.5
2000-01	13,244	12.2	11.6	12,250	12.2	11.7	25,494	52.0	48.0
2005-06	18,500	6.9	7.7	22,300	12.6	12.9	40,800	45.3	54.7
2010-11	62,301	22.4	16.3	63,843	14.2	14.7	1,26,144	49.4	50.6
2013-14	67,339	2.7	2.6	92,000	14.8	13.8	1,59,339	42.3	57.7
2020-21	1,38,875	30.6	13.0	5,29,690	68.5	34.6	6,68,565	20.8	79.2
2022-23 (RE)	2,54,799	83.4	-	1,95,929	-63.0	-	4,50,728		

Source: Gorain and Dutta (2026).



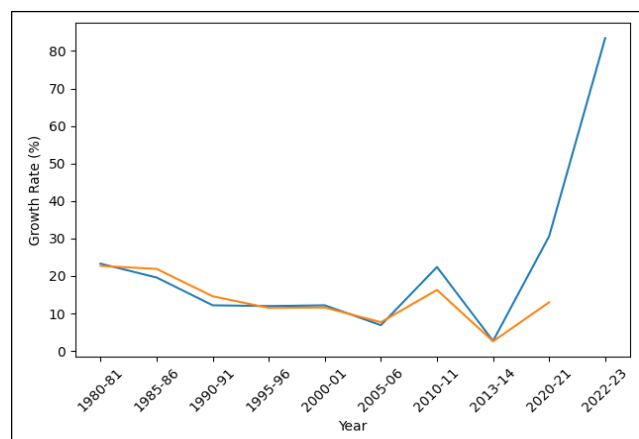
वृद्धि दर (CAGR) तथा कुल कृषि सब्सिडी व्यय में उर्वरक और खाद्य सब्सिडी के प्रतिशत हिस्से को दर्शाया गया है। विश्लेषण के अनुसार, उर्वरक सब्सिडी ₹ 7,091 करोड़ (लगभग USD 860 मिलियन) से बढ़कर 1990–91 में ₹ 2,54,799 करोड़ (लगभग USD 31 बिलियन) तक पहुँच गई, जो सरकार की वित्तीय प्रतिबद्धता के बड़े स्तर को दर्शाती है। परिणाम बताते हैं कि उर्वरक और खाद्य दोनों सब्सिडियों में निरंतर वृद्धि हुई है, जिसमें प्रमुख नीतिगत परिवर्तनों और वैश्विक मूल्य झटकों के समय विशेष तेजी देखी गई।

1976 से 1991 के बीच, उर्वरक सब्सिडी की वृद्धि दर (CAGR 14.6%) खाद्य सब्सिडी (1.2%) से अधिक रही, जो हरित क्रांति की इनपुट-आधारित रणनीति को दर्शाती है। 1990 के दशक के बाद, खाद्य सब्सिडी में तेजी आई, जिसका कारण सरकारी खरीद (procurement) में वृद्धि और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी रहा। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लागू होने के बाद खाद्य सब्सिडी का संस्थागत विस्तार हुआ, जिससे 2013–14 में इसका हिस्सा बढ़कर 57.7% हो गया। कोविड-19 महामारी के दौरान खाद्य सब्सिडी में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। (Gorain and Dutta, 2026).

आरेख 4 से पता चलता है कि उर्वरक सब्सिडी की वार्षिक वृद्धि दर (AGR) तथा चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) में समय-समय पर उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव रहे हैं। वर्ष 2010–11 तथा विशेष रूप से 2022–23 में वृद्धि दर में तीव्र बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह उर्वरक कीमतों में वृद्धि, सरकारी नीतिगत हस्तक्षेपों तथा बढ़ती सब्सिडी आवश्यकताओं का प्रतिबिंब है।

#### हाल की नीतिगत प्रगति (Recent policy developments)

- **बजटीय फोकस (Budgetary focus):** उर्वरक सब्सिडी अभी भी एक बड़ा वित्तीय बोझ बनी हुई है, जो 2022 में कुल बजट का 12% से अधिक रही और वित्त वर्ष 2024–25 में बढ़कर ₹ 1.91 लाख करोड़ हो गई, जो संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता को दर्शाती है। हाल के वर्षों में उर्वरक सब्सिडी के लिए अतिरिक्त बजटीय



**आरेख 4:** भारत में उर्वरक सब्सिडी की वार्षिक वृद्धि दर एवं चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) का विश्लेषण।

प्रावधानों की आवश्यकता पर भारत सरकार ने भी बल दिया है (PIB, 2024)।

- **पोषक-आधारित सब्सिडी (Nutrient-Based Subsidy - NBS):** भारत सरकार ने 2022–23 से 2024–25 के बीच फॉस्फेटिक और पोटाश (P&K) उर्वरकों के लिए ₹ 2.04 लाख करोड़ से अधिक की प्रतिबद्धता की है, ताकि मूल्य अस्थिरता को नियंत्रित किया जा सके।
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer - DBT):** अब सब्सिडी को निर्माता के डिस्पैच के बजाय वास्तविक बिक्री बिंदु (PoS) लेन-देन से जोड़ा गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है, लेकिन कंपनियों के लिए नकदी चक्र (Cash conversion cycle) लंबा हो गया है। उर्वरक क्षेत्र में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली के कार्यान्वयन से पारदर्शिता में सुधार हुआ है, यद्यपि आपूर्ति श्रृंखला एवं नकदी प्रवाह संबंधी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं (Mishra, 2015)।
- **सब्सिडी संरचना (Subsidy structure):** सरकार को अक्सर आयात और कच्चे माल की ऊँची लागत को देखते हुए वर्ष के मध्य में अतिरिक्त बजटीय प्रावधान करने पड़ते हैं, जैसा कि वित्त वर्ष 2025 के अंतिम बजट में वृद्धि से स्पष्ट है।

#### सब्सिडी वितरण एवं प्रवृत्तियों का विश्लेषण (Analysis of Subsidy Disbursements & Trends)

- **लगातार उच्च स्तर (Persistent highs):** सुधारों के बावजूद, सब्सिडी का स्तर संरचनात्मक रूप से उच्च बना हुआ है, जिससे सार्वजनिक वित्त पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
- **खपत में बदलाव (Shift in consumption):** नाइट्रोजन (यूरिया) का उपयोग लगातार बढ़ रहा है, जबकि सब्सिडी संरचना गैर-यूरिया क्षेत्र में मार्जिन, मात्रा और कार्यशील पूंजी को प्रभावित करती है।
- **क्षेत्रीय प्रभाव (Sector impact):** P&K उर्वरकों के लिए 90–95% तक आयात पर निर्भरता होने के कारण, अमोनिया और फॉस्फोरिक एसिड जैसे वैश्विक कच्चे माल की कीमतें सब्सिडी वितरण को काफी प्रभावित करती हैं।

#### अंतरराष्ट्रीय तुलना एवं विचार (International Comparisons and Considerations)

- **WTO बाधा (WTO Constraint):** भारत की उर्वरक सब्सिडी पर WTO के कृषि समझौते के तहत निगरानी होती है, जो इनपुट सब्सिडी को सीमित करता है।
- **दक्षता बनाम सब्सिडी (Efficiency vs. Subsidy):** अध्ययनों से पता चलता है कि सब्सिडी ने कृषि उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने में मदद की है, लेकिन यह बहस जारी है कि क्या इनपुट निर्माताओं को सब्सिडी देने के बजाय किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता दी जानी चाहिए।
- **वैश्विक मूल्य निर्भरता (Global price dependence):** भारत की सब्सिडी वितरण प्रणाली अंतरराष्ट्रीय गैस और उर्वरक कीमतों में उतार-चढ़ाव से काफी प्रभावित होती है, जो इसे उन देशों से अलग बनाती है जहाँ घरेलू प्राकृतिक गैस की उपलब्धता अधिक है।

भारतीय उर्वरक उद्योग की भविष्य की संभावनाएँ वैश्विक कच्चे माल की कीमतों, आयात निर्भरता तथा सरकारी सब्सिडी नीतियों से प्रभावित होंगी (Tradejini, 2024)।

## निष्कर्ष

यह अध्ययन 2001 से 2023 के बीच भारत की उर्वरक सब्सिडियों पर बढ़ते बोझ को रेखांकित करता है। 2001–2002 में कुल सब्सिडी ₹ 12,695.02 करोड़ से बढ़कर 2022–2023 में ₹ 2,54,798.88 करोड़ हो गई, जो वैश्विक उर्वरक कीमतों में वृद्धि और घरेलू मांग के कारण हुई है। 2010 में न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) योजना की शुरुआत पोषक तत्व-संतुलित उर्वरकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए की गई थी, लेकिन यूरिया अभी भी सब्सिडी का प्रमुख हिस्सा बना हुआ है, 2020–2021 में कुल सब्सिडी का 70% से अधिक यूरिया को आवंटित किया गया था। इस असंतुलन के कारण नाइट्रोजन-आधारित उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग हुआ है, जिससे मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरणीय स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस अध्ययन में वित्तीय बोझ को कम करने और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए नीति सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जिसमें यूरिया को NBS के तहत लाना और जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देना शामिल है। लेख उर्वरक सब्सिडी के पुनर्गठन की आवश्यकता पर जोर देता है ताकि संतुलित उर्वरीकरण सुनिश्चित हो, पर्यावरण की रक्षा हो और वित्तीय दबाव कम हो।

## संदर्भ

- Arbiya, N.A. and Zeba, S. (2022). An analysis of fertiliser subsidies in India. *Saudi J. Econ. Fin.* **6(12)**: 406-412.
- Economic Survey of India. (2022). Subsidies and Agricultural Productivity.
- Gorain, S. and Dutta, S. (2026). Trends, dynamics and policy implications of fertilizer and foodgrain subsidies in India. *Discover Food*. **6**: 129. <https://doi.org/10.1007/s44187-026-00856-6>.
- Mankunnummal, A. (2022). Containing the Fertilizer Subsidy in India: An Analysis of Subsidy Containing Strategies and Its Outcome, Working Paper 506. Centre for Development Studies (Under the aegis of Govt. of Kerala and Indian Council of Social Science Research) Thiruvananthapuram, Kerala, India.
- Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India. (2023). Fertilizer Subsidy Reports and Budget Documents.
- Mishra, G. (2015). Direct transfer of subsidies in fertilizers: Issues and challenges for supply chain. *Srusti Management Review*. **8(1)**: 76-82.
- <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NotelId=154966&ModuleId=3&reg=3&lang=2#:~:text=Fertilizer%20Subsidy%20and%20Budgetary%20Support,1%20C68%20C131%20crore%20originally%20allocated.>
- <https://www.tradejini.com/blogs/indias-fertilizer-industry-market-trends-and-future-prospects>
- <https://www.indiastat.com/table/economy/amount-subsidy-gross-disbursed-fertilisers-india-2/462385>.